



जहां सत्य होता है, वहां अहिंसा होती है और अहिंसा

होने पर हमारा जीवन सुखित होता है।

where there is truth there is non-violence and its presence secures our life.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

# दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 35 ● वर्ष : 12 ● रायपुर, मंगलवार 16 जुलाई 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

## संक्षिप्त समाचार

पुलिस अधीक्षक ने 80 पुलिस कर्मियों के तबादले आदेश जारी किये

बिलासपुर/रायपुर (विस)। जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) रजेन्ड्र सिंह ने 80 पुलिस कर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार एसआई, एसएआई और 80 आरकर्मों को इधर से उत्तर किया गया है।

हाईकर्ल एवं हायर सेकंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी रायपुर (विस)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईकर्ल एवं हायर सेकंडरी द्वितीय मुख्य/उत्तर सेकंडरी परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट [www.cgbse.nic.in](http://www.cgbse.nic.in) एवं संबंधित संस्था के पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र एक्सप्रेस के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेंशन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

## के.पी. शर्मा ओली ने चौथी बार ली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ

नेपाल (एजेंसी)। नेपाल में सीपीएन-यूप्रैमेल पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने आज चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल की सरकार को सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकाजुन खड्गो ने दी बधाई।

सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को नेपाली कांग्रेस गठबंधन सरकार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वह दोस्ती को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उसका विवर।

ओली को बधाई देते हुए, मोदी ने एसपर कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और हमारे लोगों की प्राप्ति और समृद्धि के लिए हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और विस्तारित करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। नेपाल में हाल तक प्रधानमंत्री समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं।

कांग्रेस ने यारे दिन प्रतितापूर्ण संबंध : कांग्रेस अध्यक्ष मलिकाजुन खड्गो ने भारतीय गणराज्य कांग्रेस की ओर से नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शुभकामनाएं देते हुए भारत और नेपाल के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों की बात कही है। खड्गो ने कहा कि करीबी पड़ासियों के रूप में, भारत और नेपाल मित्राता और साझेदारी के अनुरूप एवं प्रचंड इसी माह 12 जुलाई को प्रतिनिधि सभा में लोगों के बीच गहरे संबंधों की विशेषता है।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार्णे जिले में लोकमान्य तिलक टिर्पति-नामांग-यूप्रैमेल के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल रेलवे (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का विवरण मत हार गए थे। इसके विश्वास मत हार गए थे।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार्णे जिले में लोकमान्य तिलक टिर्पति-नामांग-यूप्रैमेल के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल रेलवे (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का विवरण मत हार गए थे। इसके विश्वास मत हार गए थे।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार्णे जिले में लोकमान्य तिलक टिर्पति-नामांग-यूप्रैमेल के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल रेलवे (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का विवरण मत हार गए थे। इसके विश्वास मत हार गए थे।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार्णे जिले में लोकमान्य तिलक टिर्पति-नामांग-यूप्रैमेल के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल रेलवे (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का विवरण मत हार गए थे। इसके विश्वास मत हार गए थे।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार्णे जिले में लोकमान्य तिलक टिर्पति-नामांग-यूप्रैमेल के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल रेलवे (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का विवरण मत हार गए थे। इसके विश्वास मत हार गए थे।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार्णे जिले में लोकमान्य तिलक टिर्पति-नामांग-यूप्रैमेल के एक कोच में बैठक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास आग लग गई। मध्य रेल रेलवे (सीआर) के प्रवक्ता ने बताया कि सुधर करीब 6 बजाए 30 मिनट एस-8 कोच के बैठक बाइंडिंग के कारण गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को लागूरुली ट्रेन (लण जिले में) के पास रोक दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग को दुरुत बुझा दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों का विवरण मत हार गए थे। इसके विश्वास मत हार गए थे।

गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने से मवी अफरातफरी मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में बड़ा रेल हादसा होते होते बढ़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार नामांग तिलक रामचंद्र के टार





# संपादकीय इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग महत्वपूर्ण....

## आतंकवाद को निर्णायक रूप से परास्त किया जाए

देश की अपेक्षा यह है कि आतंकवाद को निर्णायक रूप से परास्त किया जाए। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो सरकार और सुरक्षा तंत्र को अपनी अब तक की रणनीति पर सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए। छह जुलाई को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के हमले में सेना को दो जवान मारे गए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने छह दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मगर सिर्फ दो दिन बाद- आठ जुलाई की रात कुलुआ में सेना के कारवां पर आतंकवादियों ने और भी ज्यादा घातक हमला किया। इसमें पांच सैनिकों की जान गई। बीते एक महीने में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अनेक घटनाएं हुई हैं। यह याद करना उचित होगा कि पिछले नौ जून को जिस समय प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे, ठीक उसी समय जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद से ऐसी घटनाओं का एक सिलसिला बना हुआ है। यह इस बात का साफ संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का एक नया दौर आया हुआ है। इससे कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। क्या राज्य प्रशासन एवं वहां के सुरक्षा तंत्र को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि खास कर जम्मू इलाका आतंकवाद का नया अड्डा बन रहा है? आतंकवादियों के पास से जिस तरह के आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें सीमा पार से मदद मिल रही होगी। तो फिर सवाल यह उठाता है कि सीमा पर चौकसी एवं घुसपैठ रोकने के उपायों का क्या हुआ? केंद्र सरकार को यह अवश्य समझना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लगातार होने से देशवासियों के मनोबल पर चोट लगती है। अब सोच का यह कवच भी नहीं है कि अनुच्छेद 370 के कारण आतंकवाद रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है। ऐसी दलीलें ज्यादा काम की नहीं हैं कि जितने सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, उनसे ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया है। देश की अपेक्षा यह है कि आतंकवाद को निर्णायक रूप से परास्त किया जाए। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो सरकार और सुरक्षा तंत्र को अपनी अब तक की रणनीति पर सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लोगों का दिल जीतना और सीमा पार के दखल को निर्वंत्रित करना दो ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका मुकाबला किए बगैर संभवतः समस्या काबू में नहीं आएगी।

वारंदर भाट्या

यह इस समय साइबर दुनिया में चौंचों का विषय है। इंटरनेट का 96 पीसदी हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। हम इंटरनेट कंटेंट के केवल चार पीसदी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का ऐसा एक हिस्सा है जिसे सर्व इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है। डार्क वेब को आम तौर पर गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लंदन में किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता डैनियल मूर और थॉमस रिड ने 2015 में 5 सप्ताह तक 2723 लाइव डार्क वेब साइट्स की सामग्री को नजर रखी और पाया कि 57 प्रतिशत में अवैध सामग्री मौजूद थी। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है जिसमें ई-मेल, नेट बैंकिंग आते हैं। डार्क वेब को खोलने के लिए टार्क ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पॉर्न जैसी बैन चीजें उपलब्ध रहती हैं। डार्क वेब ओनियन राटार्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलासं से बचाता है और उनकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रुट और री-रुट करता है। आसान शब्दों में समझें तो वो शख्स कुछ भी करे, उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क वेब ढेर सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। यहां यूजर की इनपर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है, जिसे डिकोड करना नामुकिन है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ताकि ट्रांजेक्शन को ड्रेस न किया जा सके। कहते हैं कि डार्क वेब पर हत्या की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर्स से उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं, जो बेहद सस्ते में वो चीजें भी बेचते हैं जो बैन हैं। बहुत से लोग वहां सस्ते फैन खरीदने के



क्षकर में लाखों रुपए गंवा देते हैं। सरे विश्वविद्यालय में डा. माइकल मैकगार्यस द्वारा किए गए एक अध्ययन 'इनटू द वेब ऑफ प्राइमिट' से पता चलता है कि हालात बदतर हो गए हैं। 2016 से 2019 तक डार्क वेब लिस्टिंग की संख्या जो किसी उद्यम को नुकसान पहुंचा सकती है, 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है? सभी लिस्टिंग (ड्रग्स बेचने वालों को छोड़कर) में से 60 प्रतिशत संभावित रूप से उद्यमों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिंग डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, नशीली दवाइयां, अवैध हथियार, नकली मुद्रा, चोरी की गई सदस्यता के क्रेडेंशियल, हैक किए गए नेटफिल्क्स समेत अन्य अकाउंट खरीदे जा सकते हैं। यही नहीं, यहां ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदे जा सकते हैं जो आपको दूसरे लोगों के कंप्यूटर में संधें लगाने में मदद करते हैं। हालांकि सब कुछ अवैध नहीं है, डार्क वेब का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है। उदाहरण के लिए आप शतरंज क्लब या ब्लैकबुक में शामिल हो सकते हैं, जिसे टॉर का फेसबुक जैसा एक सोशल नेटवर्क माना जाता है। अगर आपसे संबंधित डार्क वेब पर कोई जानकारी या दस्तावेज मिलते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आपको पता चल

जाएगा कि आप जोखिम वाले स्थान पर चिन्हित हैं। अगर आपकी निजी जानकारी या ऐसी कोई जानकारी डार्क वेब पर है, जिससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, तो आप सूचना एवं प्रौद्यगिकी मंत्रालय के पोर्टल पर या पुलिस को सूचित कर अपना बचाव कर सकते हैं। डीप वेब और डार्क वेब शब्दों का इस्तेमाल कभी-कभी एक-दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। डीप वेब इंटरनेट पर मौजूद किसी भी ऐसी चीज़ को संदर्भित करता है जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया गया है और इसलिए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। डीप वेब कट्टेंट में वह सब कुछ शामिल है जो पेवॉल के पीछे है या जिसके लिए साइन-इन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। इसमें वह सभी कट्टेंट भी शामिल हैं जिसे उसके मालिकों ने वेब क्रॉलर को इंडेक्स करने से रोक दिया है। मेडिकल रिकॉर्ड, शुल्क आधारित सामग्री, सदस्यता वेबसाइट और गोपनीय कॉर्पोरेट वेब पेज डीप वेब बनाने वाली चीज़ों के कुछ उदाहरण हैं। अनुमान है कि डीप वेब का आकार इंटरनेट के 96 प्रैसदी से 99 प्रैसदी के बीच है। इंटरनेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मानक वेब ब्राउज़र के माध्यम से सुलभ है,

जिसे आम तौर पर क्लियर वेब के रूप में जाना जाता है। डार्क वेब दरअसल डीप वेब का एक उपसमूह है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है, जिसे एक्सेस करने के लिए एक विशिष्ट ब्राउज़र टोर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब का आकार वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन अधिकांश अनुमान इसे कुल इंटरनेट का लगभग 5 फीसदी बताते हैं। डार्क वेब पर नेविगेट करना आसान नहीं है। यह जगह उतनी ही अव्यवस्थित और अस्त-व्यस्त है जितनी आप उम्मीद करेंगे जहां हर कोई गुमनाम है और एक बड़ा वर्ग ठगने के लिए तैयार बैठा हो। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए टोर नामक एक अनाम ब्राउज़र का उपयोग करना आवश्यक है। टोर ब्राउज़र आपके वेब पेज अनुरोधों को दुनिया भर में हजारों यूजर्स द्वारा संचालित प्रॉक्सी सर्वर की एक सीरिज के माध्यम से कनेक्ट करता है, जिससे आपके आईपी एड्रेस को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह एक छलावे की तरह काम करता है, लेकिन इसका परिणाम एक ऐसा अनुभव होता है जो डार्क वेब जैसा ही होता है- अप्रत्याशित, अविश्वसनीय और चौंकाने वाला। पिछ कहना होगा कि डार्क वेब बिटकॉइन की बदौलत पफ-पफ रहा है, यह क्रिप्टो-करेंसी है जो दो पक्षों को एक-दूसरे की पहचान जाने बिना भरोसेमंद लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। बिटकॉइन डार्क वेब के दायरे को बढ़ाने में एक बड़ा फैक्टर रहा है। लगभग सभी डार्क वेब बिटकॉइन या किसी अन्य रूप में लेनदेन करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां व्यापार करना सुरक्षित है। ऐसी जगह स्कैमर्स और चोरों को आकर्षित करती है, लेकिन जब आपका उद्देश्य बंदूकें या ड्रग्स खरीदना हो तो आप क्या उम्मीद करते हैं। जिस तरह से इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ी हैं, आपके मोबाइल पर एक क्लिक से सरकारी योजना, बैंकिंग सेवा, कोई फर्म भरना हो या कोई भी अपडेट हो, आप हासिल कर सकते हैं। यह सुविधाएं आपके लिए काफी लाभदायक हैं। लेकिन एक खतरा भी है कि सात समंदर दूर बैठा आदमी भी आप तक सीधे पहुंच सकता है। किसी तरह के साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है। इससे बचने के लिए इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को यकीनी बनाना होगा।

## विशेष लेख

# नवजातों का समय से पहले जन्म

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि भारत में हर घंटे औसतन 345 नवजातों का समय से पहले जन्म हो रहा है यानी मां के गर्भ में शिशु का नौ महीने तक विकास होता है, तब जन्म लेता है, पर अब ऐसे स्थिति में बदलाव हो रहा है, जिससे 'प्री टर्म बर्थ' बढ़ रहे हैं। देखें तो विश्व में हर दो सेकंड में एक नवजात का समय से पहले जन्म हो रहा है। और हर 40 सेकंड में इनमें से एक की मौत हो रही है। इस गंभीर समस्या को फिल्टर्डर्स विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ता सामने लाए हैं। शोध के निष्कर्ष 'साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट' में प्रकाशित हुए हैं। नवजात शिशुओं का समय से पहले मां के गर्भ से बाहर आने जलवायु परिवर्तन के कारण माना जा रहा है। जलवायु में आ रहे ऐसे बदलाव का सीधे तौर पर संबंध बच्चों की सेहत से जुड़ा है। तापमान में निरंतर बढ़ोतरी होने से न केवल प्री टर्म बर्थ हो रहे हैं, बल्कि शिशुओं की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसी ही शोध जर्मनी के पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने 29 निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर किए। एक शोध के अनुसार, चार प्रतिशत से अधिक नवजातों की मृत्यु जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले अधिकतम और न्यूनतम तापमान से जुड़ी है। ये निष्कर्ष 'नेचर कम्युनिकेशन' पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पिछले 18 वर्षों में एक लाख 75 हजार नवजातों की मौत उन 29 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में चार फीसद में से औसतन 1.5 फीसद सालाना नवजात मौतें अत्यधिक तापमान से जुड़ी थीं। वहाँ करीब तीनवें फीसद अत्यधिक ठंड से हुई थीं। इसके अलावा, 18 वर्ष की इस अवधि में नवजात शिशुओं में गर्मी से जुड़ी 32 फीसद मौतों के लिए जलवाया परिवर्तन जबाबदेह है। इसका मतलब है कि इस दौरान नवजात शिशुओं की गर्मी से जुड़ी कुल मौतों में से 1 लाख 75 हजार से अधिक मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण मानी जा रही हैं। शोध के आंकड़े अनुसार, पहले नवजात शिशुओं का जलवायु परिवर्तन की वजह से 2001 से 2019 के दौरान औसत सालाना तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा नवजात शिशुओं की शरीर तापमान नियंत्रण की क्षमता अधरी होती है। उनका शरीर गर्मी पर काब पाने के

अजीत द्विवेदी

भारत की राजनीति इतनी विभाजित कभी नहीं रही, जितनी अभी है। पार्टीयां और नेता एक दूसरे को अब राजनीतिक प्रतिदंडी नहीं मान रहे हैं, बल्कि शत्रु मान रहे हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि सब नेता मिले होते हैं। लोग देखते भी थे कि संसद में या विधानसभाओं में या राजनीतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले नेता निजी कार्यक्रमों में एक दूसरे के गले मिलते थे। राजनीति से इतर उनके आपस में अच्छे संबंध होते थे। पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में मिलते जुलते थे, बातें करते थे। लेकिन अब यह परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। अगर कहीं पक्ष और विपक्ष के नेताओं के एक दूसरे के प्रति सद्द्वाव दिखाने की तस्वीरें या खबरें आती हैं तो आश्वर्य ही होता है। ऐसी तस्वीरें आने पर नेता घबरा भी जाते हैं कि कहीं उनके आलाकमान को यह बात बुरी न लग जाए। असल में चुनावी फायदे के लिए वैचारिक और राजनीतिक विभाजन को निजी शत्रुओं में बदलने की वजह से ऐसा हुआ। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को दुश्मन मान कर उनके खिलाफ एक सतत चलने वाले अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नेताओं को भ्रष्ट, परिवारवादी और निकम्मा ठहराना शुरू किया। इससे उनकी पार्टी के नेताओं की मजबूरी हो गई कि वे कांग्रेस और दसरी भाजपा विरोधी पार्टियों के

गई,  
को  
विवर  
व्यपक्ष  
के  
कर  
व्यपना  
यह  
पहुंच  
वालों  
कहने  
जैसे  
जो  
ट से  
उत्तर ने  
मादव  
वोट  
मादव  
देंगे  
की  
कहा  
या  
केंद्र  
रूपए  
नतौर  
र का  
नहीं

करेंगे, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। वे नगीना सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए थे। ये तीन प्रतिनिधि घटनाएं हैं, जिनसे पता चलता है कि राजनीतिक विभाजन किस स्तर तक पहुंच गया है। संसद और विधानसभाओं की राजनीति तो एरिना में ग्लैडियर्स की लड़ाई में पहले ही बदल गई थी। अब जमीनी राजनीति और मतदाता भी पार्टी लाइन पर बांटे जाएंगे। वैसे ही जैसे दुनिया भर में फुटबॉल के प्रशंसक बने हैं। सबकी अपनी पसंदीदा टीम होती है, जिसके जीतने पर वे जश्न मनाते हैं और हारने पर मारपीट करते हैं। क्या इसी तरह से अब देश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में होगा? जीता हुआ नेता उन लोगों के काम नहीं करेगा, जो उसकी पार्टी के या उसके विरोधी होंगे! इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ने अब उम्मीदवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी है कि उह्वें पता होगा कि किस बूथ पर उह्वें कितने वोट मिले हैं। पहले जब बैलेट से चुनाव होता था तो कई बूथों के बैलेट एक साथ मिला दिए जाते थे और तब उनकी गिनती होती थी, जिससे बूथवार डाटा नहीं मिल पाता था। बहरहाल, ईवीएम की इस सुविधा का लाभ उठा कर सांसद और विधायक उन मतदान केंद्रों की पहचान कर सकते हैं, जहाँ उनको कम वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं और फिर उनके साथ विकास के कार्यों में भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों की शपथ का प्रारूप इस प्रकार होता है, 'मैं'

# पार्टियां और नेता अब प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि शत्रु

अजात छ्वपदा

भारत की राजनीति इतनी विभाजित कभी नहीं रही, जितनी अभी है। पार्टियां और नेता एक दूसरे को अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं मान रहे हैं, बल्कि शत्रु मान रहे हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि सब नेता मिले होते हैं। लोग देखते भी थे कि संसद में या विधानसभाओं में या राजनीतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले नेता निजी कार्यक्रमों में एक दूसरे के गले मिलते थे। राजनीति से इतर उनके आपस में अच्छे संबंध होते थे। पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में मिलते जुलते थे, बातें करते थे। लेकिन अब यह परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। अगर कहीं पक्ष और विपक्ष के नेताओं के एक दूसरे के प्रति सद्भाव दिखाने की तस्वीरें या खबरें आती हैं तो आश्वर्य ही होता है। ऐसी तस्वीरें आने पर नेता घबरा भी जाते हैं कि कहीं उनके आलाकमान को यह बात बुरी न लग जाए। असल में चुनावी फायदे के लिए वैचारिक और राजनीतिक विभाजन को निजी शत्रु में बदलने की वजह से ऐसा हुआ। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को दुश्मन मान कर उनके खिलाफ एक सतत चलने वाले अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नेताओं को भ्रष्ट, परिवरावादी और निकम्मा ठहराना शुरू किया। इससे उनकी पार्टी के नेताओं की मजबूरी हो गई कि वे कांग्रेस और दूसरी भाजपा विरोधी पार्टियों के गलियां देने लगे ताकि अपनी स्वामीभक्ति साक्षित की जा सके। तो दूसरी ओर राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने नीतियों और सरकार के कामकाज की बजाय नरेंद्र मोदी को शत्रु मान कर सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाने की रणनीति अपना ली। पार्टियों और नेताओं के बीच शुरू हुआ यह विभाजन अब जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच गया है। अब नेता अपने खिलाफ मतदान करने वालों को अपना दुश्मन बताने लगे हैं और खुल कर कहने लगे हैं कि वे उन लोगों का काम नहीं करेंगे, जिन्होंने उनको बोट नहीं दिया। इसकी तीन मिसालें हैं, जो हाल की हैं। बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव जीते जनता दल यू.के देवेश चंद्र ठाकुर ने नतीजों के बाद कहा कि वे मुस्लिम और यादव लोगों के काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उनको बोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादव उनके पास आएंगे तो वे उनको चाय पानी करा देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। इसके बाद झारखण्ड की गोड्डा सीट से जीते भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर भाजपा को 60 फीसदी या उससे ज्यादा बोट मिले हैं वहां सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे, जिनकी लागत 50 से 60 लाख रुपए होगी। तीसरी मिसाल उत्तर प्रदेश की नतौर विधानसभा सीट से जीते भाजपा के ओम कुमार का है, जिन्होंने कहा है कि वे उन लोगों का काम नहीं थे। ये तीन प्रतिनिधि घटनाएँ हैं, जिनसे पता चलता है कि राजनीतिक विभाजन किस स्तर तक पहुंच गया है। संसद और विधानसभाओं की राजनीति तो ऐसी है में ग्लैडियर्टर्स की लड़ाई में पहले ही बदल गई थी अब जमीनी राजनीति और मतदाता भी पार्टी लाइन पर बांटे जाएंगे। वैसे ही जैसे दुनिया भर में फुटबॉल के प्रशंसक बने हैं। सबकी अपनी पसंदीदा टीम होती है, जिसके जीतने पर वे जश्न मनाते हैं और हारने पर मारपीट करते हैं। क्या इसी तरह से अब देश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में होगा? जीता हुआ नेता उन लोगों के काम नहीं करेगा, जो उसकी पार्टी के या उसके विरोधी होंगे! इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ने अब उम्मीदवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी है कि उन्हें पता होगा कि किस बूथ पर उन्हें कितने बोट मिले हैं। पहले जब बैलेट से चुनाव होता था तो कई बूथों के बैलेट एक साथ मिला दिए जाते थे और तब उनकी गिनती होती थी, जिससे बूथवार डाटा नहीं मिल पाता था। बहरहाल, ईवीएम की इस सुविधा का लाभ उठा कर संसद और विधायक उन मतदान केंद्रों की पहचान कर सकते हैं, जहां उनको कम बोट मिले हैं या नहीं मिले हैं और फिर उनके साथ विकास के कार्यों में भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों की शपथ का प्रारूप इस प्रकार होता है, ‘मैं,

अमुक, जो लोक सभा का सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं या ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा'। राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए चुने गए या मनोनीत किए गए सदस्यों के लिए भी यही प्रारूप होता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि चुना गया सदस्य देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ध्यान रहे भारत का संविधान सभी नागरिकों की समानता की बात करता है और किसी भी आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। ऐसे में संविधान को मानने वालों कोई भी व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि वह एक वर्ग के लिए काम करेगा और दूसरे के लिए नहीं करेगा? यहां एक तकनीकी पहलू है, जिसका इस्तेमाल खुलेआम भेदभाव की बात करने वाले सांसदों और विधायकों के बचाव में किया जा सकता है। वह पहलू यह है कि मर्तियों के शपथ में एक अतिरिक्त लाइन यह जोड़ी जाती है कि, 'मैं संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अच्छा व्यवहार करूँगा'। यह लाइन सांसदों और विधायकों की शपथ में नहीं होती है। क्या इससे सांसदों और विधायकों को यह छूट मिल जाती है कि वे भेदभाव कर सकें?

# भारत को प्रभावी जनसंख्या नीति की जरूरत

सत्यपाल वौशष्ट

हमें केरल राज्य के लोगों से शिक्षा भी लेनी चाहिए। जहां जनसंख्या ज्यादा है, परंतु स्थिर है क्योंकि सभी लोग छोटे परिवार को अपनाते हैं। इसकी जड़ों में शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। औरतें ही अपने परिवार का आकार छोटा रखती हैं क्योंकि वो सब शिक्षित हैं वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या 8118835999 है जो वर्ष 2023 से 0.91 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या 1441719812 है जो वर्ष 2023 से 0.92 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। भारत जनसंख्या के हिसाब से चीन को पीछे छोड़ कर विश्व में पहले नंबर पर आ गया है। चीन की वर्तमान जनसंख्या 1425181397 है। जनसंख्या में वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डालती है। मात्लबस ध्योरी के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति प्रगति से बढ़ती है तथा खाद्य उत्पादन केवल अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। मतलब अर्थिक संसाधनों में वृद्धि की गति काफ़ी कम होती है और जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। जनसंख्या वृद्धि का भार वर्तमान संसाधनों पर पड़ता है जिससे अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, अगर उत्पादकता को जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से न बढ़ाया जाए। बढ़ती आबादी से गरीबी और असमानता बढ़ती है। शिक्षा का बुनियादी ढांचा बढ़ती आबादी की जरूरतों से जूझ रहा होता है तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक चुनौती बन जाती है। बढ़ती आबादी से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है जिससे मूलभूत आवश्यकताओं और आधारभूत संरचनाओं पर दबाव बढ़ता है तथा रोजगार के अवसर और परिवहन सुविधाएं प्रभावित होती हैं।



प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती आबादी के बोझ से पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है जिससे जल की उपलब्धता भी कम हो जाती है। 2050 तक विश्व की अनुमानित जनसंख्या 9.7 बिलियन तथा जीवन प्रत्याख्या 72.6 से बढ़ कर 77.1 वर्ष हो जाएगी। इससे संसाधनों की कमी के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या संबंधी मुद्दों और सतत विकास पर उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में स्थापित यह परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकारों के महत्व को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हर साल नया थीम घोषित किया जाता है। इसी के अनुसार परे विश्व में जागरूकता

अभियान चलाया जाता है तथा इस दिशा में कार्यक्रम किया जाता है। वर्ष 2024 का थीम हमें याद दिलाता है कि समस्याओं को समझने, समाधान तैयार करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह में निवेश करना महत्वपूर्ण है। वित्त भी वैसा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि चीन की औसत वार्षिक वृद्धि दर से दुगनी से भी अधिक है, जो चिंतनीय है। भारत में शहरीकरण, साक्षरता दर के बढ़ने, देरी से विवाह, एक बच्चा या बच्चा न करने का संकल्प, औरतों का नौकरी करना, आर्थिक मजबूरी के कारण एक बच्चा, बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आदि से प्रजनन दर कम हो गई है। प्रजनन दर 1950 में 6.18 बच्चे थीं जो 2021 में 1.91 रह गई हैं जो 2.1 के आवश्यक स्तर से भी कम है। कम प्रजनन दर के दीर्घीकालीन

समय में भारत की जनसंख्या गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगे, जो सोचनीय विषय है। भारत अभी युवा देश है। यहां 27 वर्ष तक की आयु वाली आधी आबादी है तथा 27 वर्ष से ऊपर वाली भी आधी आबादी है। भारत को युवा कार्यबल की आबादी, बुजुर्गों की आबादी से ज्यादा ही बनाए रखनी है। इसलिए भारत को मौजूदा जनसंख्या नीति की पड़ताल करनी चाहिए और बढ़ती जनसंख्या के बारे में सरकार को गंभीरता से लेकर इसे नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाला है जिससे पानी की उपलब्धता मांग के बढ़ने के कारण कम हो रही है। भारत में 766 जिलों में से 266 जिलों में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली, बैंगलुरु तथा अन्य राज्यों में पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु जल संसाधन वही हैं। जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण बढ़ जाता है जिससे ठास अपशिष्ट 0.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन पैदा हो रहा है जो वर्तमान 50 करोड़ शहरी आबादी का 150000 टन प्रति दिन है। यह विकसित देशों से तीन गुणा अधिक है। शहरों के बाहर कचरा भराव क्षेत्र ने पहाड़ों का रूप ले लिया है। ये कचरे के पहाड़ टोक्सिसन का रिसाव भूतल पानी में भेजते हैं। भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है। 23 वर्ष में वर्तमान जीडीपी 3.73 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक लानी है। इसके लिए परिवार नियोजन ही जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जिम्मेदार परिवार नियोजन प्रयासों को बढ़ावा देकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में एक कमेटी बनाने की घोषणा की है।









श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

विष्णु के सुशासन से  
सँवर रहा छत्तीसगढ़

# समर्थन मूल्य और रक्खा बढ़ा 3100 लपट प्रति विंटल

की दर से  
किसानों से 21 विंटल  
प्रति एकड़ धान खरीदी



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने  
के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें ...

श्री विष्णुदेव साय  
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

## हमने बनाया है, हम ही सँवरेंगे